न्यायमूर्ति जे.एम. टंडन के समक्ष

दुली चंद - अपीलकर्ता,

बनाम

भगवंती और अन्य - प्रतिवादी.

1978 का एफ.ए.ओ. नंबर 168-एम

9 नवंबर, 1979

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का 25) विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम (1976 का 68) द्वारा संशोधित - धारा 23 (4) और 28- अधिनियम के तहत दायर गिरफ्तारी का ज्ञापन - क्या डिक्री की प्रति के साथ होना चाहिए शीट- धारा 28 का संशोधन-का प्रभाव. माना गया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री की किसी प्रति की आवश्यकता नहीं थी। असंशोधित अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान है कि सभी डिग्रियां अपील योग्य होंगी और संबंधित धारा के तहत स्थिति वही रहेगी। संशोधित अधिनियम का. डिक्री को अब मूल और नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए न्यायालय के डिक्री के रूप में अपील योग्य बना दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संशोधित कला की धारा 23 (4) के तहत, अदालतों के लिए पार्टियों को डिक्री की एक प्रति मुफ्त में प्रदान करना अनिवार्य बना दिया गया है, जहां तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग कर दिया जाता है

लेकिन यह दायित्व इसकी एक प्रति प्रदान करने की आवश्यकता या अन्यथा के संबंध में स्थिति को नहीं बदलेगा। अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संशोधित अधिनियम द्वारा संशोधन के बाद भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपील के ज्ञापन के साथ फैसले की प्रति के अलावा डिक्री की एक प्रति प्रदान करना आवश्यक नहीं है।

(पैरा 12, 14, 15 और 17)

श्री तरलोचन सिंह, एच.सी.एस. की अदालत के फैसले से पहली अपील। सब-जज प्रथम श्रेणी। रेवारी, दिनांक 29 सितंबर, 1978, ने पति/याचिकाकर्ता दुली चौधरी की पत्नी श्रीमती भवन्ती के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका को खारिज कर दिया, और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया।

दावा: दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका।

अपील में दावा: निचली अदालत के आदेश और डिक्री को उलटने के लिए।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता चंद्र सिंह।

प्रतिवादी की ओर से एच. एल. सरीन, अधिवक्ता और आर. एल. सरीन, अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति जे.एम. टंडन,

दुली चंद अपीलकर्ता और भागवंती प्रतिवादी का विवाह 14 दिसंबर, 1967 को नई दिल्ली में हुआ था। वे शादी के बाद रेवाडी में रहते थे। प्रतिवादी ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। 13 दिसंबर, 1975 को अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि दो साल पहले वह अपने माता-पिता के घर प्रसव के लिए दिल्ली गई थी। उसके बाद उसके द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद वह रेवाडी नहीं लौटी।

2. प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के साथ अपनी शादी और उससे दो बच्चों के जन्म को स्वीकार किया। उसने स्वीकार किया कि वे 15 मई, 1972 तक एक साथ रहे। उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने उसे पीटा था और उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था।

3. पार्टियों की दलील पर, निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए:

1. क्या प्रतिवादी बिना किसी उचित कारण या बहाने के याचिकाकर्ता (अब अपीलकर्ता) की सोसायटी से हट गया है।

2. क्या याचिका पार्टियों के गलत संबंध के लिए खराब है?

3. क्या याचिका नियमानुसार दायर नहीं की गई है?

4. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुद्दा संख्या 1 और 2 को प्रतिवादी के पक्ष में और मुद्दा संख्या 3 को अपीलकर्ता के पक्ष में पाया और परिणामस्वरूप याचिका खारिज कर दी। यह इस आदेश के विरुद्ध है कि वर्तमान अपील निर्देशित है।

5. अपीलकर्ता ने श्रीमती को पक्षकार बनाया था। प्रतिवादी के रूप में भागवंती की मां लिलू ने भी इस आधार पर कहा कि उन्होंने भागवंती को उसके पास नहीं भेजा था। जहां तक लिलू का सवाल है, उसके खिलाफ अपीलकर्ता के पक्ष में वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता

है। इसलिए, वह न तो आवश्यक है और न ही उचित पार्टी है। उसके खिलाफ अपीलकर्ता की याचिका सही ढंग से खारिज कर दी गई है। भागवंती प्रतिवादी के खिलाफ याचिका केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि उसकी मां श्रीमती थीं। लिलू को एक पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था।
6. प्रतिवादी ने अपने आरोप के समर्थन में कि अपीलकर्ता ने उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, रेवारी के आर.डब्ल्यू. नाथू राम को पेश किया, जिन्होंने कहा कि प्रतिवादी दो बार उनके घर आई और शिकायत की कि अपीलकर्ता ने उनका ठीक से भरण-पोषण नहीं किया और उन्हें पीटा। यह 1967 और 1971 की बात है। प्रतिवादी के पिता सूरज भान और दिल्ली के नाथू राम ने उनसे संपर्क किया और उनसे पार्टियों के बीच सुलह कराने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करने का अनुरोध किया। वह उस कारखाने में गया जहां अपीलकर्ता काम कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अपीलकर्ता से बात की, वह क्रोधित हो गया और उन्हें मारने के लिए डंडा उठा लिया। चनकंद राम ने हस्तक्षेप कर उन्हें बचाया. एक अन्य आर.डब्ल्यू. नाथू राम दिल्ली के निवासी हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रतिवादी के पिता सूरजभान के साथ रेवाड़ी गए थे। उन्होंने रेवाडी के नाथू राम से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें उस कारखाने में ले जाएं जहां अपीलकर्ता काम करता था, ताकि दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाया जा सके। वे सभी फैक्ट्री गए। फैक्ट्री के मालिक ने उन्हें बैठा लिया. अपीलार्थी को बुलाया गया। अपीलकर्ता ने उन्हें देखते ही लाठी उठाई और उस पर हमला करने ही वाला था कि उसके नियोक्ता ने उसे शांत किया और वे दिल्ली लौट आए। भागवंती प्रतिवादी ने स्वयं अपने मामले का समर्थन किया।

7. अपीलकर्ता ने इसके विपरीत साक्ष्य पेश किया और खुद गवाह के रूप में भी पेश हुआ।

8. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी की उपेक्षा की है क्योंकि उसने अपनी शादी की तारीख 15 नवंबर, 1970 बताई थी, जबकि शादी 14 दिसंबर, 1961 को हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। अपीलकर्ता का यह कथन कि वह अपने बच्चों की जन्मतिथि नहीं जानता था और यह तथ्य भी कि जब वह प्रतिवादी अपने माता-पिता के साथ दिल्ली में रहती थी तो उसने उसका भरण-पोषण नहीं किया। ये तथ्य इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए शायद ही महत्वपूर्ण हों कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ क्रूरता से व्यवहार किया या उसने उसे पीटा। दो नाथू राम के बयान कि अपीलकर्ता ने उन पर हमला करने की कोशिश की जब उन्होंने उसे सुलह के लिए बुलाया, अविश्वसनीय हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न तो सत्य है और न ही विश्वास को प्रेरित करता है। प्रतिवादी उचित कारण के साथ अपीलकर्ता के समाज से हटने पर अपीलकर्ता द्वारा उसकी उपेक्षा को साबित करने में विफल रही है। इसके विपरीत अपीलकर्ता ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिवादी बिना किसी उचित कारण के उसकी सोसायटी से अलग हो गया है। मुद्दा संख्या 1 के तहत ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष टिकाऊ नहीं होने के कारण उलट दिया गया है और अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया गया है।

9. अपीलकर्ता ने अपील के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रति दाखिल की। रजिस्ट्री ने आपत्ति की कि डिक्री-शीट दाखिल की जानी चाहिए। अपील को इस उत्तर के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया कि निर्णय ऐसे मामलों में डिक्री का एक हिस्सा है और डिक्री-शीट दाखिल न करने से अपील की संस्था अमान्य नहीं हो जाती है।
10. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अपील के साथ फैसले की एक प्रति के अलावा, डिक्री-शीट की एक प्रति दाखिल करना अपीलकर्ता के लिए अनिवार्य था और चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए अपील उत्तरदायी है। इस आधार पर बर्खास्त किया जाए। उन्होंने श्रीमती पर भरोसा जताया है। सुरजीत कौर बनाम श्री तरसेम सिंह 1977 पी.एल.आर. 667 . अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि ऐसे मामलों में डिक्री-शीट की कोई प्रति दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है और निर्णय स्वयं एक डिक्री है जिसके परिणामस्वरूप डिक्री-शीट दाखिल न करने से अपील पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिलिपि निर्णय दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने दोलित सिंह पियारा सिंह बनाम का हवाला दिया है। शमशेर कौर ने अपने तर्क का समर्थन किया।

11. दलजीत सिंह के मामले (सुप्रा) में, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अपील में डिक्री-शीट की एक प्रति दाखिल न करने के परिणाम की जांच की गई। ये हुआ था:

संहिता के अनुसार एक साधारण मुकदमे में एक न्यायाधीश को निर्णय देना होगा और उसके बाद डिक्री के रूप में औपचारिक अभिव्यक्ति होगी। लेकिन अधिनियम के किसी भी प्रावधान में ऐसा कोई पैटर्न नहीं पाया जाता है। जाहिर है, अधिनियम के तहत एक याचिका किसी मुकदमे की प्रकृति की नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यदि अधिनियम नहीं होता, तो जिन राहतों का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, उनमें से कोई भी राहत सामान्य सिविल न्यायालय में मांगी जाती, लेकिन अब जब अधिनियम है, तो उन राहतों को केवल अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही मांगा जा सकता है। , और उन प्रावधानों के तहत मुकदमे के माध्यम से राहत नहीं मांगी जाती है। अधिनियम के तहत अपील का जो भी अधिकार है, वह अधिनियम में ही धारा 28 द्वारा प्रदान किया गया है और ऐसा कोई भी अधिकार स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता में अपील के संबंध में किसी भी सीमा के अधीन नहीं किया जा सकता है... शब्द "डिक्री" को संहिता की धारा 2(2) में परिभाषित अर्थ दिया गया है और यह आवश्यक रूप से अधिनियम के तहत डिक्री पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अधिनियम के तहत डिक्री का दायरा और प्रकृति पर्याप्त रूप से और विशेष रूप से परिभाषित की गई है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान। अधिनियम की धारा 9, 10, 11 और 12 के तहत निर्णयों को उन प्रावधानों के तहत डिक्री कहा जाता है जब दावा की गई राहत दी जाती है। और चूँकि न तो धारा 2(2) और (9) और 33, न ही आदेश 41, संहिता का नियम 1 ऐसे न्यायनिर्णयन पर लागू होता है, यह सही दृष्टिकोण नहीं है कि ऐसे न्यायनिर्णयन में निर्णय के बाद औपचारिक डिक्री होनी चाहिए। संहिता के उन प्रावधानों के लिए स्पष्ट रूप से आवश्यक है... न केवल धारा 10 बल्कि अधिनियम की धारा 9, 11, 12 और 13 भी इनमें से किसी के तहत दावा की गई राहत देते समय न्यायालय को उन प्रावधानों के तहत डिक्री देने की बात

करती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब उन धाराओं में से किसी एक के तहत याचिका खारिज कर दी जाती है और राहत से इनकार कर दिया जाता है, तो उनमें से किसी एक धारा के संदर्भ में डिक्री बनाने का कोई अवसर नहीं होता है। धारा 23 की उपधारा (1) के प्रावधानों से भी यही निष्कर्ष मिलता है।

12. प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह स्पष्ट है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि दलजीत सिंह के मामले (सुप्रा) में दिए गए नियम के मद्देनजर, हिंदू विवाह के तहत अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री की किसी प्रति की आवश्यकता नहीं थी। अधिनियम, 1955। हालाँकि, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि 1976 में किए गए हिंदू विवाह अधिनियम के संशोधन ने स्थिति बदल दी है और दलजीत सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्धारित नियम को लागू करना आसान हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप इसके तहत अपील अब डिक्री की एक प्रति के साथ होनी चाहिए।

13. 1976 के संशोधन से पहले हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28 पढ़ी गई: -

इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा किए गए सभी डिक्री और आदेश उसी तरह लागू किए जाएंगे जैसे कि अपने मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए न्यायालय के डिक्री और आदेश लागू किए जाते हैं, और इसके लिए किसी भी कानून के तहत अपील की जा सकती है।
संशोधित हिंदू विवाह अधिनियम, 1974 की धारा 28 में लिखा है:

28. डिक्री एवं आदेशों से अपील :-

(1) इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दिए गए सभी डिक्री, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन होंगे। अपने मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिए गए न्यायालय के निर्णयों के रूप में अपील की जा सकती है, और ऐसी प्रत्येक अपील उस न्यायालय में की जाएगी, जिसमें मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिए गए न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील की जाती है।

(2) इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश, धारा 25 या धारा 26 के तहत, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन होंगे, अपील योग्य होंगे यदि वे अंतरिम आदेश नहीं हैं, और ऐसी प्रत्येक अपील झूठ होगी उस न्यायालय में जहां उसके मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिए गए न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें आम तौर पर की जाती हैं।

(3) केवल लागत के विषय पर इस धारा के तहत कोई अपील नहीं होगी।

(4) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील डिक्री या आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी।

14. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि संशोधित अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के तहत अब यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि न्यायालय द्वारा किए गए सभी डिक्री डिक्री के रूप में अपील योग्य होंगे और इससे पहले ऐसा नहीं था। संशोधन और इस प्रकार अब यह आवश्यक है कि डिक्री की एक प्रति अपील के ज्ञापन के साथ प्रदान की जाए। मुझे इस विवाद में कोई ताकत नजर नहीं आती. असंशोधित अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान है कि सभी डिक्री अपील योग्य होंगी और संशोधित अधिनियम की संबंधित धारा के तहत स्थिति समान रहेगी। डिक्री को अब मूल और नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए न्यायालय के डिक्री के रूप में अपील योग्य बना दिया गया है। संशोधित धारा 28, इस प्रकार इस अवधारणा में कोई बदलाव नहीं करती है कि धारा 9, 10, 11, 12 और 13 के तहत राहत डिक्री के रूप में दी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप दलजीत सिंह के मामलों में निर्धारित नियम (सुप्रा)) अच्छा बना रहेगा।
15. प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा प्रचारित एक अन्य बिंदु यह है कि संशोधित अधिनियम की धारा 23(4) के तहत अदालत के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जहां विवाह हो वहां पक्षों को डिक्री की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए। तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया। विद्वान वकील ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के लिए अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री की एक प्रति दाखिल करना अनिवार्य हो गया है। मैं इस विवाद से भी सहमत नहीं हूं. पार्टियों के विवाह को विघटित करने वाले डिक्री की एक प्रति प्रदान करने के लिए न्यायालय की ओर से दायित्व, अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री की एक प्रति प्रदान करने की आवश्यकता या अन्यथा के संबंध में स्थिति को नहीं बदलेगा।

16. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए सुरजीत कौर के मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया है कि अपीलकर्ता के लिए अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री की एक प्रति दाखिल करना आवश्यक है। उस मामले के तथ्य अब विचाराधीन मामले से पूरी तरह से अलग हैं और इसके अलावा अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री की एक प्रति आवश्यक रूप से प्रदान की जानी थी या नहीं, यह न तो सीधे तौर पर मुद्दा था और न ही उस पर फैसला सुनाया गया था। इसलिए, प्रतिवादी के विद्वान वकील इस अधिकार का कोई लाभ नहीं उठा सकते।

17. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1976 में संशोधन के बाद भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अपील के ज्ञापन के साथ फैसले की प्रति के अलावा डिक्री की एक प्रति प्रदान करना आवश्यक नहीं है।

18. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर अपील सफल होनी चाहिए और परिणामस्वरूप भागवंती प्रतिवादी के खिलाफ याचिका को खारिज करने वाले विद्वान ट्रायल कोर्ट के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को उसके खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दिया जाता है।

श्रीमती के खिलाफ याचिका खारिज करने का आदेश लीलो प्रतिवादी कायम है। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा